अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
24 अकबर रोड नई दिल्ली–110011
मीडिया विभाग

पत्रकार वार्ता के मुख्य बिन्दु बुधवार 02 नवम्बर, 2011 सायं–4.15

श्री राशिद अलवी ने पत्रकारों को संबोधित किया ।

श्री राशिद अलवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और उस पर केंद्रित करने के लिए सरकार ने मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह कहा है कि सरकारी विभागों एवं सरकारी उपक्रमों में जितनी भी खरीदारी होगी, उसमें से 20 प्रतिशत खरीदारी लघु एवं मध्यम उद्यागों से की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के घोषणा–पत्र का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो सरकार ने पूरा किया है। 20 प्रतिशत की खरीदारी में से 20 प्रतिशत (दूसरे शब्दों में कुल खरीदारी 4 प्रतिशत) ऐसे लघु एवं मध्यम उद्योगों से की जाएगी जो अनसूचित जाति एवं जन–जातियों द्वारा चलाए जा रहे होंगे। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए सरकार वचनबद्ध थी जिसे उसने पूरा किया।

इसी सन्दर्भ में पूछे गए एक प्रश्न पर कि इसमें अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं बढ़ावा दिया गया है, श्री राशिद अलवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक खासतौर से मुसलमानों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है उसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इस विषय में प्रधानमंत्री जी का 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए चल रहा है। अल्पसंख्यकों यानि मुस्लिम भाईयों के लगभग 25 से 30 लाख विद्यार्थी बच्चों को वजीफ़ा दिया जा चुका है। इसके साथ ऐसे जिले जिसमें मुसलमानों की संख्या अधिक है वहां पर सरकार ने अलग से अधिक ध्यान दिया है। ऐसे जिलों में सड़कें, अस्पताल एवं अन्य सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वहां पर सरकार लगातार काम कर रही है।

श्री राहुल गांधी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के दौरे पर दिए गए वक्तव्य पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 20–22 सालों से

भाजपा, बसपा अथवा सपा का शासन रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के शासन को याद करती है। जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है, यह स्थिति आप सभी को भली प्रकार से मालूम है। वहां पर भ्रष्टाचार का कोई हिसाब–किताब नहीं है हर स्तर पर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। उसी को लेकर श्री राहुल गांधी जी ने यह बयान दिया है।

एक अन्य प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या श्री राहुल गांधी जी को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिन पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा चल रही है, श्री राशिद अलवी ने कहा कि यह संगठन का अन्दरूनी मामला है, जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती। जैसे ही पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचेगी, आपको सूचित किया जाएगा ।

तेलंगाना पर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के प्रभारी महासचिव इस कार्य में जुटे हैं और वे ही इसकी जानकारी दे पाएंगे।

एक अन्य प्रश्न पूछे जाने पर कि आज ढाई साल प्रश्चात कांग्रेस को घोषणा–पत्र की क्यों याद आ रही है, श्री राशिद अलवी ने कहा कि पार्टी जो घोषणा–पत्र में वायदे करती है उसे पूरा करती है। अभी तीन साल का समय सरकार का बाकी है। एक–एक करके जो भी वायदे हमने जनता से किए हैं उसे पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। यह हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी वचनबद्धता भी है।

राईट टू रिजेक्ट और राईट टू रिकाल के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि राईट टू रिजेक्ट पर देश में बहस होनी चाहिए, राईट टू रिकाल पर भी देश में बहस हो सकती है, और बहस के बाद देश जिस निर्णय पर पहुंचेगा, उसको कार्यान्वित किया जा सकता है। ऐसे हालात में जबकि 60 प्रतिशत लोग वोट डालने जाते हैं, राईट टू रिकाल का कोई मतलब नहीं रह जाता।

राईट टू रिजेक्ट के बारे में भी मैं यही कह रहा हूं कि 40 प्रतिशत लोग वोट डालने नहीं जा रहे, तो सबसे अधिक जरूरी है कि सभी राजनीतिक दलों को जनता से अनुरोध करना चाहिए कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान में हिस्सा लें, इस पर बहस हो सकती है।

तेल की कीमतों में पुनः वृद्धि पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि यह कोई मज़ाक का विषय नहीं है, यह बहुत गंभीर मामला है। जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो सरकार की मजबूरी हो जाती है। 81 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल हम आयात करते हैं। हम सरकार से अनुरोध कर चुके हैं कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए जिससे आम आदमी पर अधिक बोझ न पड़े। सरकार इस पर गौर कर रही है। यह सभी प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए चाहे वे कांग्रेस प्रशासित प्रदेश हों अथवा विपक्ष शासित प्रदेश हों, अगर वे वैट सेल्स टैक्स कम करेंगे तो जनता पर बोझ कम पड़ेगा। तेल कंपनियां स्वतंत्र हैं इस विषय में फैसला करने के लिए।

मुस्लिम आरक्षण पर श्री मुलायम सिंह के बयान के विषय में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि मुलायम सिंह जी भारत–सरकार के मंत्री रह चुके हैं, उस समय उन्होंने इस विषय में क्यों कुछ नहीं किया। आज जब कि वे विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और जैसे ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही वे मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान जारी कर रहे हैं। हमने अपने घोषणा–पत्र में इसका वायदा किया था कि जो मुसलमान आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके आरक्षण का प्रावधान करेंगे। इस वायदे को पूरा करने के लिए हम अभी भी वचनबद्ध हैं और पूरा करेंगे।

आंध्र प्रदेश के सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री को राज्यसभा के सांसद के रूप में नामजद करने के विषय में पत्र के विषय में पूछे एक प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि यह मामला सीबीआई के पास चला गया है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। जो भी जिम्मेदार होंगे, उनको सजा मिलेगी।

2 दिसम्बर 2007 के मुरली मनोहर जोशी के 2जी स्पैक्ट्रम के विषय में प्रधानमंत्री को लिखे गए एक पत्र के विषय में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि जोशी जी ने पत्र में लिखा था कि अगर स्पैक्ट्रम की नीलामी की जाएगी तो इससे बीएसएनएल एवं एमटीएनएल को नुकसान पहुंचेगा इससे सही मायने में जो खरीद्दार हैं उनके हितों की रक्षा नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपने पत्र में स्पैक्ट्रम की नीलामी का विरोध किया था। आज पूरी भाजपा जुबान से कुछ और कहती है और उन्हीं के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी, जो आज पीएसी के चेयरमैन हैं, अपने पत्र द्वारा कुछ और कहते हैं। श्री राशिद अलवी ने उस पत्र की दो पंक्तियां पढ़कर मीडिया को सुनाई। उस समय के वाणिज्य की स्थाई समिति के चैयरमैन थे।

"Some operators have suggested that spectrum should be auctioned which means that could be a case of hoarding and cartelization to the detriment of MTNL and BSNL."

आज उसके विल्कुल विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। यह भाजपा के दो चेहरे हैं जो समय के साथ–साथ बदलते रहते हैं।

पीएसी की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा व्यवहार के विषय में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि मैं पीएसी की कार्रवाई के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि वो कार्रवाई गोपनीय होती है। उस पर न तो कोई राय दी जा सकती है और न ही कोई टिप्पणी की जा सकती है।

काले–धन के विषय में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि सरकार की काबिले–तारीफ है कि काले–धन के लिए उसने इतनी तेजी के साथ कदम उठाया है। इसकी तारीफ विपक्ष को भी करनी चाहिए। इन्कम–टैक्स उन तमाम लोगों के यहां छापे मार चुका है, जांच शुरू हो चुकी है, और इसके साथ–साथ सीबीडीटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वित्तमंत्री ने इस विषय में अपना बयान दिया है। यह सरकार का काबिले–तारीफे कदम है कि काले–धन को विदेश से लाने के लिए इतनी तेजी से कदम उठाए हैं और जो भी इसमें कुछ और मालूम होगा, आपको बताया जाएगा।

अन्ना हजारे टीम का आरोप लगाना कि कांग्रेस पार्टी द्वारा उनके सदस्यों के विरूद्ध मनघड़न्त कहानियां गढ़ी जा रही हैं, श्री राशिद अलवी ने कहा कि मूलरूप से उनकी कमेटी एवं सदस्यों की कोई जानकारी नहीं है। श्री राशिद अलवी ने पुनः कहा कि व्यर्थ ही श्री अन्ना हजारे जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है जबकि सरकार खुद एक सशक्त लोकपाल बिल लाने के लिए कोशिश कर रही है और आशा करते हैं कि आने वाले शीतकालीन सत्र में लोकपाल बिल को पेश किया जाएगा और उसको पास करने का अधिकार संसद का है। कोई पार्टी इस अधिकार को नहीं ले सकती। हमें आशा है कि लोकपाल बिल इस शीतकालीन सत्र में पास हो जाएगा।

(टॉम वडक्कन)
मीडिया सचिव